महायोजना में विकसित किए जाएं क्लस्टर : योगी

सीएम ने स्थानीय शिल्पकला-परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया निर्देश

राब्यू, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बुधवार को उनके सरकारी आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़ तथा मथुरा-वृंदावन जिलों की महायोजना 2031 का प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने प्रत्येक जिले की महायोजना में स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित करने का निर्देश दिया। सभी नगरों में इनर रिंग रोड के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने इसके बगल में विभिन्न लिंक रोड पर सुविधाएं विकसित करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की आवश्यकताओं का व्यापक अध्ययन कर महायोजना में उनका ध्यान रखना होगा। नगर के अंदर भीड़भाड़ को दूर करने के लिए रिंग रोड के बाहर अलग-अलग मार्गों पर अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों का विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। शहरी क्षेत्रों में प्लानिंग करते समय स्वयं के स्रोतों से आय सृजित करने की व्यवस्था हो। नगरों में यातायात प्रबंधन के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। मल्टीलेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास ही लाजिस्टिक हब भी तैयार किया जाए। योगी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्राथमिकता के साथ कराने के लिए कहा। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर नगर की महायोजना में हरित क्षेत्र आरक्षित हो। सभी विकास प्राधिकरणों में अंतराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राधिकरण/स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/अवैध रिहायशी कालोनी बसने न पाए। विकास प्राधिकरणों को नई संभावनाएं तलाशनी होंगी। नगर निगम के बाहर विस्तार लेना होगा। अपना दायरा बढ़ायें। आय के नए स्रोत सृजित करने होंगे।

- सीएम के समक्ष अलीगढ़, मेरठ, आजमगढ़, गोरखपुर, व मथुरा-वृंदावन की महायोजनाओं प्रस्तुतीकरण
- मुख्यमंत्री ने कहा-विकास प्राधिकरणों में बनाए जाएं अंतराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर

लोक भवन में आयोजित मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में सुभाष कुमार प्रजापति को टूल किट का प्रमाण पत्र देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में मंत्री राकेश सचान • जागरण

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा उप्र

राब्यू, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्र को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से सेमीकंडक्टर नीति बनाने के लिए कहा है। यह भी निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में निवेश के लिए आने वाली इकाइयों को वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि तकनीकी युग में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका है। वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विश्व भर में 950 बिलियन डालर से अधिक का राजस्व था। इस क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों से 500 बिलियन डालर से अधिक निवेश करने की घोषणा की है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए। निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रोत्साहन दिए जाने का निर्णय लिया है।

'प्रदेश में अब 10 प्लेज पार्क'

राब्यू, लखनऊ : एमएसएमई इकाइयों को ऋण वितरण कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्लेज योजना के तहत प्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों की स्वीकृति दिए जाने के बाद इस योजना के अंतर्गत 10 पार्क मंजूर किए जा चुके हैं। एमएसएमई इकाइयों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध हैं। प्रदेश की ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाओं को अपना कर केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी है।

अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2022-23 में पहली अप्रैल से 31 दिसंबर तक एमएसएमई इकाइयों को 1,11,448 करोड़ ऋण दिया गया। वहीं 2023-24 के दौरान इसी अवधि में उन्हें 1,73,846 करोड़ का ऋण वितरण हुआ।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कौशांबी में नए सीएफसी के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा। ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाओं के पांच लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए। माटी कला बोर्ड की ओर से दो कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक भेंट किए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली तीन महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी भी सौंपी। ओडीओपी योजना की काफी टेबल बुक का विमोचन किया।